



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 24 23 ज्येष्ठ 1940 (श0)  
पटना, बुधवार, 13 जून 2018 (ई0)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4-बिहार अधिनियम	---
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9-विज्ञापन	---
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	4-10

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचनाएं

29 मई 2018

सं० भा०व०से०(स्था०)—11/2016-1552/प०व०—श्री हेम कान्त राय, भा०व०से०, (BH:2004), वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रवर कोटि (वेतन स्तर-13 रुपये 1,23,100-2,15,900) में दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

सं० भा०व०से०(स्था०)—11/2016-1553/प०व०—श्री सुनील कुमार, भा०व०से०, (BH:2004), वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद वन प्रमंडल, औरंगाबाद को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रवर कोटि (वेतन स्तर-13 रुपये 1,23,100-2,15,900) में दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रत्नेश झा, संयुक्त सचिव।

29 मई 2018

सं० भा०व०से०(स्था०)—11/2016-1554/प०व०—भारतीय वन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों के आवंटन वर्ष में संशोधन के फलस्वरूप उन्हें पूर्व में स्तंभ-4 के अनुरूप स्वीकृत उप वन संरक्षक का प्रवर कोटि वेतनमान (37,400-67,000, GP-87,00) में देयता तिथि को स्तंभ-5 के अनुरूप संशोधित किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	पूर्व में स्वीकृत प्रवर कोटि वेतनमान की देयता तिथि एवं तत्संबंधी अधिसूचना संख्या/दिनांक	प्रवर कोटि वेतनमान की संशोधित देयता तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री कुन्दन कुमार	2000	01.01.2014 1410/06.05.2015	30.01.2013
2.	श्री मनोज कुमार सिंह	2000	01.01.2014 1618/05.06.2014	30.01.2013
3.	श्री पी०के० जायसवाल	2000	16.02.2015 1412/06.05.2015	30.01.2013

4.	श्री के०के० अकेला	2000	16.02.2015 1413 / 06.05.2015	30.01.2013
----	-------------------	------	---------------------------------	------------

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रत्नेश झा, संयुक्त सचिव।

सं० 398

**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

**प्रभार- प्रतिवेदन**

31 मई 2018

अधोहस्ताक्षरी, मैं श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (2000) आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-1/पी.-1004/2018- सा.प्र.-6953 दिनांक 29.05.2018 के आलोक में दिनांक 31.05.2018 के पूर्वाह्न में सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पद का प्रभार ग्रहण करता हूँ।

विनय कुमार,  
भारमुक्त पदाधिकारी।

जितेन्द्र श्रीवास्तव,  
भारग्राही पदाधिकारी।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय**  
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**  
**बिहार गजट, 12-571+10-डी०टी०पी०।**  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**

# बिहार गजट

## का

## पूरक(अ0)

## प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

5 जून 2018

सं0ग्रा0वि0-14(तिरहुत)मुजफ्फरपुर-03/2017-373146/ग्रा0वि0—श्री अमरेन्द्र पंडित, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मड़वन, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध दोषी पंचायत सेवक को बचाने का प्रयास करने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने संबंधी आरोपों पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक- 1033 दिनांक 21.02.2017 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-303744 दिनांक 09.03.2017 द्वारा श्री पंडित से स्पष्टीकरण की माँग की गई एवं प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-352099 दिनांक 05.02.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से मंतव्य हेतु अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से प्राप्त मंतव्य में श्री पंडित के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप की पुनः पुष्टि की गयी है।

उक्त संदर्भ में श्री पंडित के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के मंतव्य के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री पंडित द्वारा साक्ष्य जुटाने एवं आरोप प्रपत्र 'क' गठित करने में विलम्ब किया गया है।

अतएव सम्यक् विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री पंडित को 'चेतावनी' की सजा दी जाती है।

श्री पंडित को अधिरोपित उक्त शास्ति को इनके चारित्र्य/सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राधा किशोर झा, अपर सचिव।

सं0(सं0सं0-ग्रा0वि0-14(मुं0)खग0-01/2015)-373289

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

6 जून 2018

सुश्री रीना कुमारी, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया सदर सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी, मधेपुरा के विरुद्ध संकल्प ज्ञापांक- 340835 दिनांक 05.12.2017 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए श्री विनोद कुमार, तत्कालीन विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

श्री विनोद कुमार के स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके स्थान पर संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री राजेश परिमल, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को नामित किया जाता है।

संकल्प ज्ञापांक- 340835 दिनांक 05.12.2017 के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

आदेश:--आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राधा किशोर झा, अपर सचिव।

सं0 08/नि0था0-11-06/2014,सां0प्र0-4334

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

3 अप्रैल 2018

श्री उमाशंकर राम, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1132/08, 899/11 के विरुद्ध आय के ज्ञातश्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति अर्जित करने के आरोपों पर निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पदस्थापन काल में आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या-31/2013 दिनांक 17.07.2013 दर्ज किये जाने एवं इस क्रम में प्रत्यानुपातिक धनार्जन का साक्ष्य प्राप्त होने की सूचना महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक 468/गो० दिनांक 18.07.2013 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। मामले की गंभीरता के मद्देनजर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12560 दिनांक 29.07.2013 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से श्री राम को निलंबित किया गया। जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्राप्त आरोप, प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप प्रपत्र 'क' पुनर्गठित करते हुए संकल्प ज्ञापांक 4244 दिनांक 28.03.14 द्वारा श्री राम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी यथा आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 841 दिनांक 02.03.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें प्रोपर्टी रिटर्न में घोषित सम्पत्ति के विवरण से अधिक सम्पत्ति पाये जाने का आरोप स्पष्ट रूप से प्रमाणित बताया गया। विभागीय पत्रांक-12580 दिनांक 25.08.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री राम से लिखित अभिकथन की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में यह पाया गया कि श्री राम ने अपने बचाव बयान में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे स्पष्ट हो सके कि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पाया गया चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण उनके वैध आय के श्रोतों के अन्दर है एवं वार्षिक रिटर्न में विधिवत् रूप से घोषित थी। उनके इस आचरण को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-iii के प्रतिकूल पाये जाने, भ्रष्ट आचरण की पुष्टि होने तथा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा-13 (2) सह पठित धारा-13 (1) (ई०) के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई विचाराधीन रहने के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित आरोपों के लिए राज्यमंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6626 दिनांक 01.06.2017 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी (जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी) का दंड संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश को निरस्त करने हेतु श्री राम ने अपना पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (दिनांक 14.07.2017) समर्पित किया, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से उल्लेख किया कि उनके लिखित अभ्यावेदन एवं अनुपूरक लिखित अभिकथन पर विचार किये बिना ही दंडादेश पारित किया गया। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई की गयी। उनके विरुद्ध दर्ज कांड में अन्तिम निर्णय के पूर्व ही विभागीय कार्यवाही में दंडादेश पारित कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है।

आरोपित पदाधिकारी के पुनर्विलोकन अर्जी (दिनांक 14.07.17) में निहित तथ्यों की गहन समीक्षा में निम्न तथ्य उजागर हुए :-

(क) विभागीय संकल्प सं०-2324 दिनांक 10.07.2007 द्वारा यह परिचारित है कि आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों के विरुद्ध स्वतंत्र विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि आपराधिक कार्यवाही के अपील या रिवीजन में यदि सजा से मुक्त भी कर दिया जाता है तो विभागीय कार्यवाही में दोष सिद्ध होने पर दी गयी सजा कायम रखी जा सके।

समान आरोपों पर आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही चलायी जा सकती है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय भी पारित है।

इस प्रकार श्री राम का कथन यथा, “आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज कांड में अन्तिम निर्णय लिये जाने के पूर्व ही विभागीय कार्यवाही में दंडादेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है” स्वीकार योग्य नहीं है।

(ख) श्री राम के विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन तथा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्राप्त आरोप, प्रपत्र ‘क’ के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के उपरांत आरोपों की प्रमाणिकता का मंतव्य समर्पित किया। विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए दंडादेश संसूचित किया गया। इस क्रम में पुनर्विलोकन अर्जी में कोई नया तथ्य नहीं पाया गया।

वर्णित स्थिति में श्री राम के पुनर्विलोकन अर्जी (दिनांक 14.07.2017) को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6626 दिनांक 01.06.2017 द्वारा पारित आदेश (सेवा से बर्खास्तगी (जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी)) यथावत रखा जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-190/2014,सां०प्र०-4346  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

3 अप्रैल 2018

श्री शाहिद परवेज, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-927/11 के विरुद्ध जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में कतिपय अनियमितता (गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचित मुखिया और शिक्षा मित्र के नियोजन एवं ऑगनबडी सेविका की नियुक्ति में अनियमितता बरतने वाले मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करना) बरतने संबंधी आरोप जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-88,मु०/गो०, दिनांक 12.07.2014, पत्रांक-2046/गो०, दिनांक 06.07.2014 एवं पत्रांक-2265, दिनांक 22.07.2014 के द्वारा प्राप्त हुआ। माननीय लोकायुक्त के स्तर पर भी उक्त आरोपों के लिए दायर परिवाद से उदभूत वाद में सुनवाई हुई। जिला स्तर से प्राप्त सभी आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर समेकित आरोप, प्रपत्र ‘क’ गठित किया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6198, दिनांक 24.04.2015 द्वारा मामले की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी यथा, आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को प्रमाणित बताया गया। इस क्रम में श्री परवेज का लिखित अभिकथन (पत्रांक-03, दिनांक 05.01.2016) प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने प्रमाणित आरोपों पर बचाव बयान प्रस्तुत करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया। समीक्षा में यह पाया गया कि माननीय लोकायुक्त के स्तर पर संचालित वाद की सुनवाई के क्रम में ससमय अनुपालन एवं अन्य दायित्व निर्वहन में श्री परवेज से चूक हुई। सम्यक् विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3327 दिनांक 03.03.2016 द्वारा निन्दन (आरोप वर्ष-2011-12 के प्रभाव से) एवं एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक संबंधी दंड संसूचित किया गया है।

2. उपर्युक्त दंड पर पुनर्विचार हेतु श्री परवेज ने अपना अभ्यावेदन (पत्रांक-36 दिनांक 12.01.2017) समर्पित किया। जिसमें आरोपों पर बचाव करते हुए मुख्य रूप से वाद सं०-5/लोक (शिक्षा) 14/2010 में माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 23.09.2016 को पारित आदेश को आधार स्वरूप प्रस्तुत किया। जिसमें विभागीय दंडादेश पर पुनर्विचार की अनुशंसा की गयी थी। कालान्तर में वाद सं०-1/लोक(कल्याण)44/2008 में माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 28.10.2016 को पारित आदेश में विभागीय स्तर से श्री परवेज को संसूचित दंड को औचित्यपूर्ण माना। सम्यक समीक्षा के उपरांत श्री परवेज का पुनर्विचार अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री शाहिद परवेज, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-927/11 को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3327 दिनांक 03.03.2016 द्वारा संसूचित दंड (निन्दन (आरोप वर्ष-2011-12 के प्रभाव से) एवं एक वेतन वृद्धि की असंचयात्मक प्रभाव से रोक) यथावत् रखा जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-66/2016,सां०प्र०-5292

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

18 अप्रिल 2018

इन्दिरा आवास आवंटन में अनियमितता संबंधी परिवाद से उद्भूत वाद सं०-01/लोक(पंचायत)155/10 में माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 07.02.2018 को पारित अंतरिम आदेश में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास (मधुबनी) श्री बिन्देश्वरी प्रसाद को निलंबित करने की अनुशंसा की गयी, जो लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1245 दिनांक 15.02.2018 द्वारा प्राप्त हुआ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (1) (क) में निहित प्रावधानों के तहत श्री बिन्देश्वरी प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-424/11, सम्प्रति उप विकास आयुक्त, अरवल को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2.निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3.निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

4.संदर्भित आरोपों की जाँच हेतु इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन का आदेश अगल से निर्गत किया जायेगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-189/2014 सां०-5326

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

19 अप्रिल 2018

श्री प्रहलाद लाल, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-773/11 के विरुद्ध कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सासाराम के पदस्थापन काल से संबंधित जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक-817 दिनांक 21.03.2013 द्वारा प्रतिवेदित आरोप (वर्ष-2011-12 में विधि व्यवस्था संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने) नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-1228 दिनांक 17.05.2013 के माध्यम से कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त के आलोक में विभागीय स्तर पर गठित आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न करते हुए श्री लाल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। एतदसंबंधी विभागीय पत्रांक-487 दिनांक 09.01.2015 के क्रम में प्रेषित स्मार पत्रांक-12544 दिनांक 26.09.2017 के अनुपालन में श्री लाल, सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बेनीपुर ने आरोपों पर बचाव प्रस्तुत करते हुए अपना स्पष्टीकरण (यथा, पत्रांक-877 दिनांक 18.10.2017) समर्पित किया। विभागीय पत्रांक-14976 दिनांक 27.11.2017 द्वारा संदर्भित स्पष्टीकरण पर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त स्तर से प्रेषित मंतव्य (पत्रांक-761 दिनांक 08.02.2018) में श्री लाल के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा को यथावत् रखा गया। सम्यक् समीक्षा के उपरांत इस मामले में वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

2.अतएव यह निर्णय लिया गया है कि श्री लाल के विरुद्ध अनुलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों की वृहद जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सासाराम द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे।

3.श्री लाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-66/2016, सां०प्र०-5333  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

19 अप्रैल 2018

श्री बिन्देश्वरी प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-424/11 के विरुद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास, मधुबनी के पद पर पदस्थापन के दौरान वर्ष 2007-2008 में इन्दिरा आवास आवंटन में अनियमितता बरतने संबंधी श्री मिलन कामत एवं अन्य के परिवाद पत्र के आलोक में लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना के स्तर पर वाद सं०-01/लोक (पंचायत)155/10 संचालित हुआ। उक्त आरोपों के लिए श्री प्रसाद के विरुद्ध कार्रवाई हेतु ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 293716 दिनांक 09.12.2016 द्वारा आरोप प्रपत्र-‘क’ उपलब्ध कराया गया। कालान्तर में विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप प्रपत्र-‘क’ की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 9850 दिनांक 02.08.2017 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इस हेतु पुनः विभागीय पत्रांक 11421 दिनांक 04.09.2017 द्वारा स्मारित भी किया गया, परन्तु स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। संदर्भित वाद में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथियों पर श्री प्रसाद के बार-बार अनुपस्थित रहने की स्थिति में माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 07.02.2018 को अंतरिम आदेश पारित कर उन्हें (श्री बिन्देश्वरी प्रसाद को) निलंबित करने की अनुशंसा की, जो लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1245 दिनांक 15.02.2018 द्वारा प्राप्त हुआ। सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (1) (क) में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5292 दिनांक 18.04.2018 द्वारा श्री बिन्देश्वरी प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-424/11, उप विकास आयुक्त, अरवल को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया। माननीय लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश की गम्भीरता एवं श्री प्रसाद द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के आलोक में इस मामले के वृहद जांच की आवश्यकता पायी गयी।

2. अतएव यह निर्णय लिया गया है कि श्री प्रसाद के विरुद्ध अनुलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों की वृहद जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे।

3. श्री प्रसाद से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 06/आ.-53/2016 (छाया)-सा.प्र.-6648

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

22 मई 2018

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, भा.प्र.से. (बिहार : 2005), संयुक्त सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के बिहार प्रशासनिक सेवा की सेवावधि में सहायक प्रशासक, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम, पटना के पदस्थापन काल में चाणक्य टावर एवं चाणक्य होटल के भवनों के करारोपन में बरती गयी अनियमितताओं के आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-521 दिनांक 15.01.2014 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा पटना उच्च न्यायालय में सी.डब्लू.जे.सी. संख्या-3194/14 दायर किया गया और माननीय न्यायालय के पारित दिनांक 18.12.15 के अंतरिम आदेश द्वारा उक्त विभागीय संकल्प संख्या-521 दिनांक 15.01.2014 तथा संगत आरोप प्रपत्र-‘क’ को निरस्त कर दिया गया और आदेश के विरुद्ध में राज्य सरकार द्वारा एल.पी.ए. संख्या-435/2016 दायर किया गया। दिनांक 18.12.2015 के पारित आदेश के अनुपालन किये जाने के लिए आरोपित पदाधिकारी द्वारा अवमानना वाद संख्या-383/2016 दायर किया गया और उक्त वाद में दिनांक 29.02.2016 के पारित अंतरिम आदेश



के आलोक में राज्य सरकार द्वारा विचारोपरांत श्री सिंह के विरुद्ध गठित प्रपत्र—‘क’ तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक—521 दिनांक 15.01.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के निर्णय को निरस्त (set aside) करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3910 दिनांक 14.03.2016 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र—‘क’ एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक—521 दिनांक 15.01.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के निर्णय को निरस्त (set aside) किया गया।

3. इस बीच में राज्य सरकार के उक्त निर्णय के उपरांत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (भारत सरकार) के दिनांक 04.05.2016 की अधिसूचना द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, बि.प्र.से. (कोटि क्रमांक—318/11) भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किये गये।

4. एल.पी.ए. संख्या—435/2016 में दिनांक 12.12.2017 को सुनवाई करते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा सी.डब्लू.जे.सी संख्या—3194/14 में दिनांक 18.12.2015 को पारित आदेश पर अगले आदेश तक स्थगन आदेश दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पारित अंतरिम आदेश के संदर्भ में विधि विभाग/विद्वान महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त किया गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय के उक्त दिनांक 12.12.2017 के अंतरिम आदेश एवं विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचार किया गया।

5. माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 12.12.2017 के पारित अंतरिम आदेश एवं विधि विभाग/विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के परामर्श के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3910 दिनांक 14.03.2016 को रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

साथ ही, चूँकि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, भा.प्र.से., तत्कालीन सहायक प्रशासक, नूतन राजधानी, पटना नगर निगम के विरुद्ध तत्समय बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्य रहने की स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अधीन आरोप पत्र निर्गत कर एवं आरोपित से स्पष्टीकरण प्राप्त कर संचालन पदाधिकारी/जाँच पदाधिकारी की नियुक्ति करने की कार्रवाई की चुकी थी, इसलिए श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के भा.प्र.से. में नियुक्त हो जाने के पश्चात् अब उसी स्टेज से गठित आरोपों पर जाँच के लिए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम—8(6) के अंतर्गत जाँच किये जाने के लिए फिर से पूर्व में नामित जाँच पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना एवं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नामित प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को बरकरार रखते हुए जाँच कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक—3910 दिनांक 14.03.2016 को रद्द किया जाता है और श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक प्रशासक, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम सम्प्रति संयुक्त सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के भा.प्र.से. में प्रोन्नत होने के कारण अब अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम—7(1)(a)(1) को संदर्भगत करते हुए उक्त नियमावली के नियम—8(6) के अन्तर्गत आरोपों की जाँच हेतु आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा नगर विकास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

7. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, भा.प्र.से. (बिहार:2005), तत्कालीन सहायक प्रशासक, नूतन राजधानी अंचल, नगर निगम, पटना जाँच पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प की प्राप्ति होने की तिथि से 10 (दस) कार्य दिवसों में अथवा 10 (दस) कार्य दिवसों के बाद विहित किसी समय या उससे अनधिक दस दिनों के अंदर किसी समय जैसा जाँच पदाधिकारी आदेश दें, स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के साथ उपस्थित होंगे।

**आदेश :-**आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सभी सुसंगत कागजातों यथा विभागीय संकल्प संख्या-521 दिनांक 15.01.2014 सहित आरोप प्रपत्र-‘क’ एवं संगत अभिलेख आदि की प्रति संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, भा.प्र.से.(बिहार:2005), संयुक्त सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय। साथ ही, नगर विकास एवं आवास विभाग को निदेशित किया जाता है कि विभाग के किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
दयानिधान पाण्डेय, अपर सचिव।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय**  
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**  
**बिहार गजट, 12-571+10-डी0टी0पी0।**  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**